अमित शाह ने मुख्यमंत्री की पीठ थपथपाई, पेपर लीक समाप्त करने की प्रशंसा की

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आरपीए में आयोजित समारोह में आठ हजार नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्त पत्र दिए

जयपुर, 10 जनवरी। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पारदर्शी तरीके से लोकसेवकों की भर्ती करने से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को इससे निजात दिलाई है। उन्होंने कहा कि हमारी राज्य सरकार

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आज़ादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत व कुशल नेतृत्व मिल रहा है।**

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को आरपीए में आयोजित कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह को संबोधित किया।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान करते हुए राजस्थान के युवाओं को 'बिना सिफारिश और बिना खर्चे' के नौकरी दे रही है।

शाह शनिवार को आरपीए में कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी कानून व्यवस्था से ही प्रदेश का विकास संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पेपरलीक पर रोक लगाने के साथ-साथ कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को पूरे देश में निवेश का अग्रणी राज्य बनाने का काम भी किया है। इसी का परिणाम है कि आज देशभर के निवेशक राजस्थान की ओर आने की स्पर्धा कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल रहा है। धारा 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती देने का काम किया गया। शर्मा ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने नक्सलवाद का सफाया करते हुए देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया।

शाह ने कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से 10 आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम में 8 हजार से अधिक आरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में बने मल्टी परपज इंडोर हॉल का वर्चुअल लोकार्पण किया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढ़ म, सांसद मदन राठौड़, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सहित जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधिकारीगण, बड़ी संख्या में नव नियुक्त कांस्टेबल एवं उनके परिजन उपस्थित थे।

पुणे निगम चुनाव के लिए सुप्रिया व अजित पवार ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया

मुंबई, 10 जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष अजीत पवार और राकांपा (एसपी) की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शनिवारको पुणे के शिवाजीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी

- **भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्य होने के बाद भी अजित पवार ने केन्द्र व राज्य सरकार की आलोचना की**

किया। इस संयुक्त घोषणापत्र में पुणे में मुफ्त मेट्रो और बस यात्रा का वादा किया गया है।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, ''पुणेवासी सवाल कर सकते हैं कि क्या मुफ्त मेट्रो और बस यात्रा संभव भी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह संभव है। हमने विशेषज्ञों से बात करने के बाद इस बारे में फैसला किया है। हम पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ के निवासियों को मुफ्त मेट्रो रेलवे और बस यात्रा प्रदान करेंगे।''

घोषणापत्र में पुणे नगर निगम के स्कूलों के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने के साथ-साथ पुणे में 150 मॉडल स्कूल स्थापित करने का वादा किया गया है।

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, ''पुणे के पांच साल के विकास का मुद्दा हमारे सामने है। मुफ्त यात्रा प्रदान करना संभव है। क्योंकि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के प्रशासन में कुछ गलतियां हैं, जिन्हें दूर किया जाएगा।''

देवली में तीन करोड़ रूपए का गांजा जब्त

देवली/टोंक, (निसं)। टोंक की डिस्ट्रिक्ट स्पैशल टीम (डी.एस.टी.) ने ट्रक में ले जाया जा रहा करीब तीन करोड़ रुपये का गांजा जब्त करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।

देवली पुलिस थाना प्रभारी दौलतराम गुर्जर ने बताया कि टोंक डीएसटी टीम ने देवली शहर के हाईवे 52 पर नाकाबंदी करके एक ट्रक की तलाशी लेते समय गांजे की बड़ी खेप बरामद की है। जब्त किए गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग तीन करोड़ रुपये है।

पुलिस ने बताया कि पुलिस ने तस्करों को दबोचते हुए 500 किलो गांजे से भरा 12 चक्का ट्रक जब्त

- **पुलिस ने नाकाबंदी कर उड़ीसा से आ रहे ट्रक में 500 किलो गांजा पकड़ा।**

किया है। देवली पुलिस थाना प्रभारी दौलत राम गुर्जर ने यह भी बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव, पुष्पेंद्र सोलंकी और डीएसपी हेमराज के सुपरविजन में उपनिरीक्षक ओमप्रकाश की टीम ने देवली हाईवे पर घेराबंदी की थी। इसी के चलते पुलिस को देखते ही तस्करों ने ट्रक को टोंक की ओर भगाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन टीम ने पीछा करके देवली डीएसपी ऑफिस के सामने ट्रक को पकड़ लिया। पुलिस टीम ने मौके से चालक हरिनारायण, पुत्र हीरालाल मीणा, निवासी दाता ढाणी थाना देवली व समीर मीणा पुत्र रामकिशन, निवासी बासनी थाना हिण्डोली जिला बूंदी को गिरफ्तार किया है।

पूछताछ में दोनों आरोपियों ने गांजा उड़ीसा के चांदीपुर से लाना तथा हनुमानगर देवली में सप्लाई देना बताया, जिसके बाद छोटे सप्लायर के माध्यम से भीलवाड़ा, बून्दी, केकड़ी, देवली, दूनी, घाड, टोडारायसिंह, मालपुरा, डिग्गी, टोंक में नशे की सप्लाई की जानी थी।

ईरान में खामनेई विरोधी प्रदर्शनकारियों पर मशीनगन से गोलियां चलाईं

गोलीबारी में 217 प्रदर्शनकारी मारे गये, सरकार विरोधी आंदोलन और उग्र हुआ

तेहरान, 10 जनवरी। तेहरान में ईरान सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों में हिंसा बढ़ गई है। प्रदर्शन उग्र होता देख ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने का आदेश दे दिया। इस गोलीबारी में 217 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है।

दरअसल, एक स्थानीय डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर टाइम पत्रिका को बताया कि राजधानी के सिर्फ छह अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज हुई है। इसमें अधिकांश की मौत गोली लगने से हुई

- **अगर मृतकों की संख्या की सही पुष्टि हो जाती है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि सरकार 28 दिसंबर से सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारियों को मारती है, तो उसे इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।**

है। प्रदर्शनकारियों की मौत को लेकर स्थानीय डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में अधिकतर युवा थे, जिनमें उत्तरी तेहरान के एक पुलिस स्टेशन के बाहर सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करने के दौरान मारे गए कई लोग शामिल थे। इन सभी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, वाशिंगटन डीसी स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी, जो सिर्फ पहचाने गए पीड़ितों की गिनती करती है, उसने विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत से अब तक कम से कम 63 मौतों की पुष्टि की है।

ईडी सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी।

हैरानी की बात यह है कि ईडी ने राज्य की सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि अपेक्षाकृत मामूली राहतें ही मांगीं-जैसे एजेंसी को अपना काम करने देने की अनुमति। केन्द्र सरकार ने भी बेहद नरम रुख अपनाया और कानून के ऐसे स्पष्ट उल्लंघन के बावजूद आरोपी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए औपचारिक रूप से कोई कदम नहीं उठाया। यदि कोई आम नागरिक ऐसा करता, तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता।

लेकिन ममता बनर्जी के मामले में ऐसा कुछ भी प्रभावी या प्रासंगिक कदम नहीं उठाया गया। उनके खिलाफ कोई गंभीर आरोप तय नहीं किए गए। गंभीर अपराधों की जांच में बाधा डालने के बावजूद उन्हें पूर्ण प्रतिरक्षा मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके बजाय पूरे विवाद को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राज्य भाजपा इस बात की निंदा कर रही है कि एक निजी कंसल्टेंसी फर्म किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रही है और कुछ नौकरशाहों को एक निजी फर्म को रिपोर्ट करना पड़ता है।

कई करोड़ रुपये के गंभीर कोयला घोटाले सबूतों की चोरी और उन्हें नष्ट करने का एकमात्र ठोस आरोप भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक आकस्मिक प्रेस वार्ता में लगाया था। इसके बाद उस आरोप को आगे नहीं बढ़ाया गया और न ही उसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया गया।

इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर अनियमितताओं की आशंका के पर्याप्त कारण थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ईडी की तलाशी और जब्ती कार्रवाई के खिलाफ काफी जल्दबाज़ी और दुस्साहसी प्रतिरोध दिखाया। वह एक हरी फाइल को इस तरह पकड़े रहीं मानो वह उनके लिए जीवन-मरण का प्रश्न हो।

यह सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या भाजपा और ममता बनर्जी के बीच किसी तरह के गुप्त समझौते हैं, जबकि बाहर से जांच और छापों का दिखावा किया जा रहा है। राज्य में अवैध कोयला खनन का पैमाना और इसमें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की संलिप्तता तो सर्वविदित है।

ट्रंप ने ईरान में सैन्य हस्तक्षेप के संकेत दिए

परन्तु ट्रंप ने यह भी कहा कि वह ज़मीन पर सैनिक नहीं उतारेंगे

वॉशिंगटन, 10 जनवरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को कहा कि अगर ईरान वर्तमान अशांति के इस दौर में लोगों को मारना शुरू कर देता है तो अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा, हालांकि वह जमीन पर अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा।

ईरान की स्थिति पर संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा कि अगर वे लोगों को मारना शुरू करते हैं, तो ऐसा होने पर अमेरिका अपनी भूमिका निभायेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका अपनी फौजें, ईरान की जमीन पर उतार देगा। इसका अर्थ यह है कि उन्हें वहां बहुत जोर से मारना है, जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। ट्रम्प और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने

- **ट्रंप ने कहा कि ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही जनता पर हमला किया गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा।**

बार-बार चेतावनी दी है कि यदि ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, तो वॉशिंगटन कार्रवाई करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अशांति के बारे में ट्रम्प प्रशासन की टिप्पणियों को हस्तक्षेपवादी और भ्रामक बताते हुए उनकी निंदा की थी। ईरान का कहना है कि ये बयान ईरानी लोगों के प्रति अमेरिका की निरंतर शत्रुता को दर्शाते हैं।

ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी

कोलकाता, 10 जनवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को एक पत्र लिखकर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान आम नागरिकों के साथ किए जा रहे निरंतर उत्पीड़न पर हैरानी और पीड़ा व्यक्त की है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में आरोप लगाया है कि इस पुनरीक्षण अभ्यास के कारण 77 मौतें, आत्महत्या के चार प्रयास और कम से कम 17 लोगों के बीमार होने व अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई

- **बनर्जी ने नोबल पुरुस्कार विजेता अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी, फिल्म एक्टर व सांसद दीपक अधिकारी जैसी कई हस्तियों का मुद्दा उठाया, जिन्हें चुनाव आयोग के सामने अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी।**
- **मुख्यमंत्री ने टाइप की हुई चिट्ठी के साथ एक हस्तलिखित नोट भी भेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ''मुझे'' पता है आप ना तो जवाब देंगे ना ही स्पष्टीकरण देंगे पर विवरण देना मेरा कर्तव्य है।**

है। उन्होंने कहा, ''ये घटनाएं डर, डराने-धमकाने और अत्यधिक कार्यभार के कारण हुई हैं, जो आयोग द्वारा किए गए एक अनियोजित अभ्यास का परिणाम है।'' बनर्जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन, प्रसिद्ध कवि जॉय गोस्वामी, लोकप्रिय फिल्म अभिनेता और सांसद दीपक अधिकारी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी और भारत सेवाश्रम संघ के महाराज, जिन्हें नागरिकता के सत्यापन के लिए तलब किया गया है, के मामलों का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या यह आयोग की ओर से सरासर ढि ठाई नहीं है। उन्होंने कहा कि कई आम नागरिक भी इसी तरह के उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं।

प्र.मंत्री ने राज्यों के मुख्य सचिवों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जी.एस.टी. आज की कामकाज से जुड़ी कई कमियों से जूझ रहा है। रिफंड मिलने में देरी, नियमों का जटिल पालन और केन्द्र व राज्यों के बीच बार-बार होने वाले मतभेद। खासकर छोटे कारोबारियों के लिए ये समस्याएं नकदी की कमी और प्रशासनिक थकान का कारण बनती हैं। इन अड़चनों को दूर किए बिना और ज्यादा बदलाव करने से कर प्रणाली पर भरोसा लौटने के बजाय अविश्वास और बढ़ सकता है।

श्रम सुधार भी ऐसा ही विरोधाभास दिखाते हैं। दर्जनों कानूनों को चार श्रम संहिताओं में बदलना प्रशासनिक रूप से तर्कसंगत और बदलाव लाने वाला कदम है। लेकिन राज्यों द्वारा नियम अधिसूचित नहीं करने से इसका अमल रुका हुआ है, जो राजनीतिक और सामाजिक संवेदनशीलताओं को दर्शाता है। तेज़ सुधार निवेशकों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन श्रम बाज़ार में वैधता और स्वीकार्यता भी ज़रुरी है। भरोसेमंद सुरक्षा, परामर्श और अमल की क्षमता के बिना ये सुधार एकतरफा माने जा सकते हैं, भले ही उनका मकसद समावेशी विकास (इन्क्लूसिव ग्रोथ) और रोजगार सृजन हो।

सरकार कुछ हद तक सही संकेत देती है कि यह सुधार चक्र संकट से प्रेरित होने के बजाय आकांक्षा से प्रेरित है और इसमें कुछ सच्चाई भी है। भारत की जनसंख्या संरचना, बढ़ता घरेलू बाज़ार और डिजिटल ढांचा मजबूत आधार देते हैं। लेकिन केवल आकांक्षा से संस्थागत तैयारी की कमी ूरी नहीं हो सकती। ज़िला प्रशासन, नगर निकाय और राज्य नियामक, जो सुधारों को ज़मीन पर लागू करते हैं, अक्सर स्टाफ, विशेष कौशल और डिजिटल क्षमता की कमी से जूझते हैं। प्रशासनिक क्षमता में निवेश किए बिना तेज़ और गुणवत्तापूर्ण नतीजों की उम्मीद सुधारों के असर को कमज़ोर कर सकती है और निराशा बढ़ा सकती है।

निजी क्षेत्र के लिए परमाणु ऊर्जा खोलने जैसे बड़े कदम सरकार की मंशा की गंभीरता दिखाते हैं। लेकिन निजी पूंजी बहुत सख्त मानकों पर काम करती है। उसे साफ नियम, भरोसमंद विवाद, समाधान व्यवस्था और स्थिर नीतिगत माहौल चाहिए। घोषणाओं के साथ विस्तृत नियमावली और संस्थागत भरोसा भी होना चाहिए वरना इनके बदले निवेश आने की जगह सर्तकता और झिझक ही देखने को मिलेगी।

व्यापार समझौते भी बिखरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर व्यावहारिक सोच दिखाते हैं। लेकिन व्यापार उदारीकरण के साथ समायोजन की लागत आती है। लॉजिस्टिक्स, कौशल विकास और सस्ते ऋण में समानांतर निवेश के बिना, खासकर छोटे भारतीय उद्योग खुलते बाज़ार में टिक नहीं पाएंगे।

आखिरकार, इस सुधार चक्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके फायदे आम लोगों तक पहुंचते हैं या नहीं। अगर विकास के साफ तौर पर रोजगार, आय में बढ़ोतरी और क्षेत्रीय संतुलन नहीं दिखता, तो सुधारों के लिए जरुरी सामाजिक और राजनीतिक सहमति कमज़ोर पड़ सकती है।

रफ्तार ज़रुरी है। लेकिन अगर 2025 को एक ऐतिहासिक साल के रुप में याद किया जाना है, तो यह इसलिए होगा क्योंकि सुधारों को समझदारी से लागू किया गया, संस्थानों को मजबूत किया गया और जनता का विश्वास हासिल किया गया, केवल इसलिए नहीं कि वे तेज़ चले।

ओडिशा में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जा रहा है कि चार यात्रियों और दो पायलटों को ले जा रहे सिंगल-इंजन वाले इस विमान में करीब चार से पांच किलोमीटर उड़ने के बाद तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण पायलट को विमान की क्रैश-लैंडिंग करानी पड़ी।

प्रधानमंत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

10:15 बजे मंदिर में पूजा करेंगे और सुबह 11 बजे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे।बयान में कहा गया है कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत के उन अनगिनत नागरिकों को याद करने के लिए आयोजित किया जा रहा है।

एसआई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मामले से जुड़े अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि पेपर लीक से जुड़ी एसआई भर्ती-2021 में शामिल कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एकलपीठ की ओर से इस भर्ती को रद्द करने के आधार पर साल 2025 की एसआई भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की गुहार की थी। एकलपीठ ने तीस अक्टूबर, 2025 को इन अभ्यर्थियों को भर्ती में तीन साल की छूट देने को कहा। वहीं राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश जारी कर गत 13 नवंबर को एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी।

भारत-अमेरिका व्यापारिक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अध्यक्ष एस. सी. रल्हन ने निर्यात जगत की बढ़ती चिंता को व्यक्त करते हुए कहा, दोनों पक्षों को बातचीत की मेज़ पर बैठकर लंबित मुद्दों का समाधान करना चाहिए, ताकि एक पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता किया जा सके। निर्यातकों के अनुसार, मौजूदा शुल्क मुनाफे के मार्जिन को कम कर रहे हैं, अनुबंधों में बाधा डाल रहे हैं और भारतीय कंपनियों को या तो नुकसान झेलने या फिर वियतनाम, मैक्सिको और अमेरिका के अन्य वरीयताप्राप्त व्यापार साझेदार देशों के प्रतिस्पर्धियों के सामने बाज़ार में हिस्सेदारी छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

भारत के कुल वस्तु निर्यात का लगभग पाँचवाँ हिस्सा अमेरिका को जाता है। इसमें वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, ऑटो कंपोनेंट्स और रसायन जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्र शामिल हैं। इनमें से कई क्षेत्रों के मुनाफे का मार्जिन बहुत कम होता है, और वे शुल्क वृद्धि के प्रति अत्यंत संवेदनशील हैं। निर्यातकों का कहना है कि 50 प्रतिशत टैरिफ से भारतीय सामान बाज़ार से बाहर हो जाएगा।

उद्योग को इससे भी अधिक चिंता इस बात की है कि यदि बातचीत ठप्प बनी रही तो शुल्क में और बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे किसी भी अतिरिक्त टैरिफ से उस समय निर्यात बुरी तरह प्रभावित होगा, जब वैश्विक मांग पहले से ही सुस्त है और भू-राजनीतिक तनाव आपूर्ति शृंखलाओं को खंडित कर रहे हैं। छोटे निर्यातकों, विशेषकर एमएसएमई के लिए, लंबे समय तक बनी अनिश्चितता के कारण ऑर्डर रद्द हो सकते हैं, छँटनी और कार्यशील पूंजी पर दबाव पड़ सकता है।

हालाँकि, इस समझौते को अंतिम रूप देना आसान नहीं होगा कई विवादास्पद मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। अमेरिका कृषि उत्पादों, डेयरी, चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल व्यापार के बाजार में घुसना यह चाहता है, साथ ही बौद्धिक संपदा संरक्षण और डेटा लोकलाइज़ेशन मानदंडों को लेकर भी उसकी चिंताएँ हैं। वॉशिंगटन लगातार औद्योगिक वस्तुओं पर कम शुल्क और भारत की नियामक व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता की माँग करता रहा है।

वहीं भारत दंडात्मक शुल्क से राहत, हाल के वर्षों में खोई हुई वरीयताप्राप्त बाज़ार पहुँच की बहाली और वीज़ा व्यवस्थाओं के तहत कुशल पेशेवरों की अधिक आवाजाही चाहता है। नई दिल्ली उन संवेदनशील क्षेत्रों-विशेषकर कृषि और डेयरी-की रक्षा को लेकर भी सतर्क है, जहाँ राजनीतिक और सामाजिक कारणों से रियायत की गुंजाइश बेहद सीमित है। इन प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना सावधानीपूर्ण क्रमबद्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की माँग करेगा।

निर्यातकों का तर्क है कि भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह इस समझौता पहले से भी अधिक जरूरी हो गया है। जैसे-जैसे वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ चीन से दूर हो रही हैं, भारत के पास अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद विनिर्माण और सोर्सिंग केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करने का अवसर बढ़ गया है। लेकिन एक स्थिर और पूर्वानुमान लगाए जा सकने योग्य व्यापार ढाँचे के बिना यह अवसर हाथ से निकल सकता है। जिन प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के पास अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते या वरीयताप्राप्त पहुँच है, वे पहले से ही इस बदलाव का लाभ उठा रही हैं।

देरी से प्रतिष्ठा को भी नुकसान होता है। व्यवसाय वर्षों पहले निवेश और आपूर्ति अनुबंधों की योजना बनाते हैं। शुल्क और बाज़ार पहुँच को लेकर लंबी अनिश्चितता भरोसे को कमजोर करती है, क्षमता विस्तार को हतोत्साहित करती है और दीर्घकालिक व्यापार साझेदार के रूप में भारत की छवि को नुकसान पहुँचाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा घटकों और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में-जहाँ भारत निर्यात बढ़ाने की उम्मीद करता है-नीतिगत स्पष्टता लागत प्रतिस्पर्धा जितनी ही महत्वपूर्ण है।

उद्योग संगठनों का मानना है कि चरणबद्ध या सीमित व्यापार समझौता एक व्यावहारिक रास्ता हो सकता है। शुल्क युक्तिकरण, मानकों की पारस्परिक मान्यता और विवाद निपटाने पर केन्द्रित 'प्रारंभिक सौदे' सौदे निर्यातकों को त्वरित राहत दे सकते हैं और बाद में एक व्यापक समझौते के लिए भरोसा भी बना सकते हैं।

आखिरकार, निर्यातक ज़ोर देते हैं कि निष्क्रियता से होने वाले नुकसान की लागत लगातार बढ़ रही है। मुनाफे के मार्जिन घट रहे हैं और प्रतिस्पर्धा तीव्र हो रही है-हर तिमाही की देरी का मतलब है ऑर्डर ओर जमीन खो देना। एक निर्यातक ने कहा, व्यापार समझौते अब प्रतीकात्मक नहीं रहे; वे हमारे अस्तित्व का सवाल बन चुके हैं।

भारत और अमेरिका के लिए, एक व्यापार समझौता न केवल द्विपक्षीय व्यापार को स्थिर करेगा, बल्कि वैश्विक बाज़ारों को भी एक सशक्त संकेत देगा। ज़मीनी स्तर पर निर्यातकों के लिए, यह टिके रहने और पिछड़ जाने के बीच का अंतर हो सकता है।

कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। कांग्रेस ने मनरेगा की जगह नया कानून लाने के मोदी सरकार के कदम को रोजगार की इस महत्वपूर्ण योजना पर बुलडोजर चलाना करार दिया और कहा कि पार्टी ने इसके खिलाफ पूरे देश में मनरेगा बचाओ संग्राम शुरु कर दिया है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शनिवार को यहां एक बयान में कहा कि ''कांग्रेस ने आज देशभर के प्रत्येक जिला इकाई के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत कर दी। कांग्रेस इस संघर्ष को निर्णायक परिणाम तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार द्वारा जब तक मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर छीने गए काम के अधिकार, आजीविका और जवाबदेही को पूरी तरह बहाल नहीं करा लिया जाता कांग्रेस इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि हाल में पारित वीबी-जी राम जी एक्ट के रूप में आये नये कानून से मनरेगा की मूल भावना खत्म हो गई है। अब काम की गारंटी कानूनी अधिकार नहीं रह गई बल्कि केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गई है। मनरेगा खत्म करने से ग्राम पंचायतों की ताकत बहुत कमजोर हुई है और मजदूरी की गारंटी तथा समय पर भुगतान पर सवाल उठ रहे हैं।

महाराष्ट्र में नए समीकरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सीट बंटवारे में भी सहयोगी दलों की वास्तविक ताकत झलकती है। शिवसेना (यूबीटी) 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मनसे 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) इस नए गठबंधन के तहत केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की घोषणा के लिए हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे भाइयों ने मराठी मानूस को एक सशक्त संदेश देते हुए कहा, बटेंगे तो कटेंगे, यानी बंटे तो हारेंगे, एकजुट रहे तो जीतेंगे। यह नारा उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के इस्तेमाल किए गए नारे से प्रेरित होकर दिया।

भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट) गठबंधन ने मराठी मानूस के बीच मजबूत पकड़ बना ली है। एस्केंडिया स्ट्रैटैजीस के एक सर्वे के मुताबिक, इस समुदाय का वोट अब 44-42 प्रतिशत के अनुपात में बंट चुका है। वहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण उद्धव ठाकरे की पार्टी को जो मुस्लिम वोट मिला था, वह एमवीए से अलग होने के बाद स्वत: ठाकरे खेमे में आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।

इसके अलावा पवार परिवार के प्रतिद्वंद्वी गुट भी धीरे-धीरे करीब आते दिख रहे हैं। एनसीपी (अजित पवार गुट) और एनसीपी (शरदचंद्र पवार गुट) ने पुणे नगर निगम और पिंपरी-चिंचवाड़ नगर निगम के चुनाव एक साथ लड़ने का फैसला किया है। यह संकेत है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर पारिवारिक रिश्तों को तरजीह मिल सकती है। इन घटनाक्रमों ने महाराष्ट्र में बड़े राजनीतिक फेरबदल को लेकर अटकलें और तेज कर दी हैं। काफी समय से यह चर्चा चल रही है कि वरिष्ठ पवार गुट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में शामिल हो सकता है, जहां अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति संभालेंगे और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दी जा सकती है।

अपने लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में शरद पवार संभवत: अपनी बेटी सुप्रिया का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, खासकर तब जब उन्हें अजित पवार के स्तर का जनाधार वाला नेता नहीं माना जाता। शुरुआती बातचीत में दोनों गुटों के एक ही चुनाव चिन्ह पर लड़ने की संभावना पर भी विचार हुआ था, लेकिन शरद पवार गुट के इनकार से यह स्पष्ट हो गया कि अभी पूरी सुलह नहीं हुई है।

फिर भी, यह सीमित सहयोग दोनों के हित में है, खासकर पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों में खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए, जो कभी एनसीपी के मजबूत गढ़ हुआ करते थे।

2017 में भाजपा ने इन दोनों नगर निगमों पर कब्जा जमाकर एनसीपी को दूसरे स्थान पर धकेल दिया था। हाल के विधानसभा चुनावों में भी इन दो जिलों में भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीतीं, जिससे साफ है कि इस क्षेत्र में एनसीपी का पतन लगातार हो रहा है। पवार गुटों का यह गठबंधन इसी रुझान को पलटने की कोशिश है।

रणनीतिक कारण भी अहम हैं। एनसीपी के दोनों गुट संभवत: भाजपा के बिना भविष्य की राजनीति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यह अटकलें भी हैं कि भाजपा 2029 के चुनाव अकेले लड़ सकती है, जिससे अजित पवार गुट हाशिये पर चला जाएगा। ऐसे में चाचा के गुट से संवाद बनाए रखकर अजित पवार भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ अपनी राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।

इस तरह, ये नगर निकाय चुनाव न सिर्फ संगठनात्मक ताकत की परीक्षा होंगे, बल्कि राजनीतिक रणनीतियों की भी कसौटी साबित होंगे। ठाकरे परिवार के लिए यह अस्तित्व और विरासत का सवाल है, जबकि पवारों के लिए खोई हुई जमीन वापस पाने और भविष्य के विकल्प सुरक्षित करने की लड़ाई। इन चुनावों